जीने के
मजे
जीने की
जंजाल
छोड़ने में है।
-महात्मा गांधी-

दैनिक
लोकजीवन
www.lokjeewan.com
जयपुर एवं भीलवाड़ा से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी त्रिवेदी

लोक जीवन में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें:-
- : जयपुर : -
0141-4038281
- : भीलवाड़ा : -
8306792625

वर्ष- 19 | अंक- 207 | जयपुर. गुरुवार . | 26 नवम्बर , 2026 | RNI No. RAJHIN/2008/26744 | मूल्य 1 रूपया | पृष्ठ - 4

न्यूज इनबॉक्स

एक साल में चार सीजेआई! 2027 में न्यायपालिका में बनेगा नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। साल 2027 में भारत चार मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई) का गवाह होगा। इनमें से एक तो मौजूदा जेआई सूर्यकांत ही हैं, जो 9 फरवरी 2027 को सीजेआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत में 6 साल और 7 महीने तक अपनी सेवाएं दी हैं। अपने इस कार्यकाल में, उन्होंने 1 साल और 2 महीने तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा एक-एक करके सीजेआई का पद संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के आंकड़ों के अनुसार, 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई थे। इसके बाद के वर्षों में कभी एक, कभी दो तो कभी तीन-तीन सीजेआई बने। 2002 में पहली बार सबसे ज्यादा 4 सीजेआई बनाए गए। इसके बाद अब 2027 में भी चार सीजेआई के बनेंगे। जब कोई जज सीजेआई बनता है, तब तक उनके पास बेंच पर काम करने के लिए केवल कुछ साल या महीने ही बचे होते हैं। 2027 में यह स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। सीजेआई सूर्यकांत के रिटायर होने के बाद जस्टिस विक्रमनाथ सितंबर 2027 तक यानी 7 महीने के लिए सीजेआई रहेंगे। वहीं, जस्टिस विक्रमनाथ के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना जब पद संभालेंगी, तब उनके रिटायरमेंट में केवल 36 दिन बचे होंगे। जस्टिस नरसिम्हा अक्टूबर 2027 में पद संभालेंगे और मई 2028 तक इस पद पर रहेंगे। पूर्व सीजेआई पी. सदाशिवम ने भी इस बात को माना है। वे जुलाई 2013 से अप्रैल 2014 के बीच नौ महीने तक इस पद पर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि सीजेआई का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। खबरों के अनुसार, उन्होंने कहा था, 'ऐसी कई चीजें थीं जो मैं करना चाहता था, लेकिन कम कार्यकाल की वजह से नहीं कर सका।'

उमर-शरजील को फिलहाल राहत नहीं, जमानत पर मांगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। दोनों आरोपियों ने कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा कि अभियोजन पक्ष अब तक संरक्षित गवाहों की गवाही दर्ज नहीं करा पाया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी समाप्त होने के करीब है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने से पहले वह संबंधित पक्ष यानी दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगी। उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए तारीख देने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि पीठ को मामले के तथ्यों की जानकारी है और उसने इसके लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा, हमने अपना होमवर्क कर लिया है।

ऑस्कर की रेस में शामिल रणबीर कपूर की 'रामायण'

नई दिल्ली (एजेंसी)। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है। अपने वीएफएक्स को लेकर इसे काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिला है। अब 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में भी विजुअल इफेक्ट्स श्रेणी में अवॉर्ड के लिए इसने टॉप 20 फिल्मों में अपना स्थान सुरक्षित किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नितेश तिवारी की 'रामायण- राइज ऑफ ए लेजेंड' 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में टॉप 20 कंटेंडर्स में शामिल हो गई है। 'ड्यून- पार्ट थ्री', 'द ओडिसी' और 'एवेंजर्स- डूम्सडे' जैसे बड़े हॉलीवुड प्रोडक्शन्स के साथ इसका मुकाबला है। कई सूत्रों ने बताया कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की विजुअल इफेक्ट्स ब्रांच ने थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले अगले राउंड में आगे बढ़ने वाली 20 फिल्मों की लिस्ट जारी की है। ये सभी फिल्में अब वोटिंग के अगले राउंड में पहुंच गई हैं। फिल्म 'रामायण' अभी ऑस्कर के फाइनल नॉमिनेशन तक नहीं पहुंची है। अगर फिल्म आगे चलकर आधिकारिक शॉर्टलिस्ट और फिर नॉमिनेशन तक पहुंचती है तो यह भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बता दें कि टॉप 20 फिल्मों में शामिल होकर 'रामायण' का मुकाबला हॉलीवुड की कई बड़ी और चर्चित फिल्मों से है, जिसमें डेनिस विलेन्यूवे की 'ड्यून-पार्ट थ्री', क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', स्टीवन स्पीलबर्ग की 'डिस्क्लोजर डे' और मार्वल स्टूडियोज की एंथनी और जो रूसो की 'एवेंजर्स- डूम्सडे' शामिल हैं। डिज्नी चार एंट्रीज के साथ कन्फर्म्ड टाइटल्स में सबसे आगे है।

बहुमत का गणित फेल, क्रॉस वोटिंग ने बदली चुनावी तस्वीर

क्रॉस वोटिंग ने बिगाड़े सियासी समीकरण, कांग्रेस ने 24 और भाजपा ने 10 जिलों में बनाए जिला प्रमुख, बीएपी को 2 और आरएलपी को 1 जिला

जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस के यशवीर सूरा निर्वाचित

जयपुर। जिला परिषद् जयपुर के जिला प्रमुख पद के निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी यशवीर सूरा निर्वाचित हुए। निर्वाचन के लिए आयोजित बैठक में जिला परिषद के 57 निर्वाचित सदस्यों में से 56 सदस्य उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं रिटर्निंग अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि जिला प्रमुख पद के निर्वाचन के लिए भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 22 के निर्वाचित सदस्य राजेश कुमार गुर्जर तथा कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 28 के निर्वाचित सदस्य यशवीर सूरा ने नामांकन-पत्र प्रस्तुत किए थे। संवीक्षा के बाद दोनों प्रत्याशियों के नामांकन-पत्र वैध पाए गए। मतदान के उपरांत हुई मतगणना में यशवीर सूरा को 42 तथा राजेश कुमार गुर्जर को 14 मत प्राप्त हुए। हृह्रञ्ज के पक्ष में कोई मत नहीं पड़ा। इसके बाद यशवीर सूरा को जिला परिषद् जयपुर के जिला प्रमुख पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया तथा नियमानुसार शपथ दिलाई गई।



जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद् जयपुर के उप जिला प्रमुख पद का निर्वाचन गुरुवार, 26 नवंबर को जिला परिषद कार्यालय, जयपुर में आयोजित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रात: 10 बजे बैठक प्रारंभ होगी। प्रात: 11 बजे तक नामांकन-पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्रात: 11 बजे से 11:30 बजे तक नामांकन-पत्रों की संवीक्षा तथा प्रात: 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस लेने की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद आवश्यक होने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान करवाया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी निर्वाचित सदस्यों को अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।



क्रम.	जिला	विजेता	
1.	जयपुर	यशवीर सूरा	कांग्रेस
2.	जोधपुर	प्रमिला चौधरी	कांग्रेस
3.	उदयपुर	हिमत सिंह झाला	भाजपा
4.	अलवर	अमित मीणा	कांग्रेस
5.	अजमेर	पुजा भंसाली	भाजपा
6.	सीकर	सुशील गंदाल	कांग्रेस
7.	बीकानेर	मोहाराम	कांग्रेस
8.	नागौर	भागीरथ	आरएलपी
9.	भरतपुर	रेणु बाला	कांग्रेस
10.	ड़ीग	रेणु सिंह	भाजपा
11.	धौलपुर	अमित सिंह	कांग्रेस
12.	राजसमंद	सुधा देवी	कांग्रेस
13.	दौसा	बीना बैरवा	कांग्रेस
14.	झुंझुनू	ममता गुर्जर	भाजपा
15.	बांसवाड़ा	सुशील यादव	भाजपा
16.	भीगंगानगर	इंदजीत यादव	भाजपा
17.	पाली	सीमा देवी	भाजपा
19.	चित्तौड़गढ़	रश्मि देवी	कांग्रेस
10.	भीलवाड़ा	कैलाश चंद मीणा	कांग्रेस
13.	बाँगोड़ा	कांग्रेस	
14.	झालिलास	कांग्रेस	
15.	पाली	सीमा देवी	
16.	चित्तौड़गढ़	कांग्रेस	
17.	बाड़मेर	कांग्रेस	
18.	झालोर	कांग्रेस	
19.	बालापुर	कांग्रेस	
10.	भीलापुर	कांग्रेस	
12.	सीकर	कांग्रेस	
14.	गीनपत	कांग्रेस	
17.	रामबिलस	देवी	
18.	सीलादी	कांग्रेस	
19.	चित्तौड़गढ़	आरएलपी	
21.	बाड़मेर	गफूर अहमद	कांग्रेस
22.	जैसलमेर	सरोज कुमारी	कांग्रेस
23.	सवाई माधोपुर	आशा देवी	कांग्रेस
24.	फलोदी	पथवंत कँवर	कांग्रेस
25.	प्रतापगढ़	इन्द्रा कुमारी	भाजपा
26.	जालोर	आशू राम	कांग्रेस
27.	सलूंबर	पुष्पा देवी	कांग्रेस
28.	टोंक	अलका जैरवा	कांग्रेस
29.	झालावाड़	उर्मिला	भाजपा
30.	बूंदी	कविता सिंह	भाजपा
31.	चूंदी	इला गुर्जर	कांग्रेस
32.	डीडवाना-कुचामन	मुन्नालाल	कांग्रेस
33.	हनुमानगढ़	रेणु	कांग्रेस
34.	डूंगरपुर	अनुश्रिया	बीटीपी
35.	बांसवाड़ा	रेखा	बीटीपी
36.	दूदू	कोमल बंरिया	कांग्रेस
37.	सिरोही	गुलाब सिंह	कांग्रेस

जयपुर (कासं)। राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद जिला प्रमुखों के चुनाव में बहुमत का गणित कई जिलों में ध्वस्त हो गया। जिला परिषद सदस्य चुनाव में जिस पार्टी के पास संख्या बल था, वह हर जगह जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल नहीं कर सकी। क्रॉस वोटिंग और आखिरी समय में बने राजनीतिक समीकरणों ने कई जिलों में चुनावी नतीजों की तस्वीर बदल दी। निर्वाचन आयोग के जारी आंकड़ों के अनुसार, 37 जिलों में हुए जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने 24 जिलों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 10 जिलों में सफलता मिली। आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने दो जिलों में जिला प्रमुख बनाए। वहीं, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने नागौर में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। जिला प्रमुख चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह रहा कि जिला परिषद में बहुमत होना कुर्सी की गारंटी नहीं है। कांग्रेस को 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन चूरू में बहुमत के बावजूद भाजपा की कनिका सिंह जिला प्रमुख निर्वाचित हो गईं। दूसरी ओर भाजपा को पांच जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन ब्यावर में कांग्रेस की ममता गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी निर्मला रावत को एक वोट से पराजित कर दिया। इन दोनों नतीजों ने क्रॉस वोटिंग और सदस्यों के पाला बदलने की भूमिका को चर्चा में ला दिया।

कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत वाले अधिकांश जिलों में अपनी स्थिति बरकरार रखी। अलवर से अनीता मीणा, बाड़मेर से गफूर अहमद, भरतपुर से रेनू बाला, भीलवाड़ा से कैलाश मीणा, बीकानेर से निकिता डूडी, बूंदी से हंसा गुर्जर, चित्तौड़गढ़ से रतनी देवी, दौसा से बीना बैरवा, धौलपुर से अनीशा सिंह, हनुमानगढ़ से रेनू जांगू, जयपुर से यशवीर सूरा, जैसलमेर से संतोष कुमारी, जालोर से आसू राम, झुंझुनूं से कोमल भंवरिया, जोधपुर से प्रमिला चौधरी, कोटपूतली-बहरोड़ से रामनिवास यादव, फलोदी से यशवंत कंवर, राजसमंद से सुंदर देवी और सवाई माधोपुर से आशा देवी जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं। इसके अलावा सीकर से सुनीता गठाला, सिरोही से गुमान सिंह देवड़ा और टोंक से अलका बैरवा ने जीत हासिल की। दौसा, जैसलमेर और सवाई माधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। हालांकि, चूरू में पार्टी के बहुमत के बावजूद भाजपा की कनिका सिंह की जीत कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रही। कनिका सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू हैं। भाजपा को अजमेर, ब्यावर, झालावाड़, पाली और उदयपुर में स्पष्ट बहुमत मिला था। इनमें अजमेर से पूजा भंसाली, झालावाड़ से वर्षा झाला, पाली से सीता बावरी और उदयपुर से हिम्मत सिंह झाला जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। लेकिन ब्यावर में भाजपा का बहुमत काम नहीं आया। यहां कांग्रेस की ममता गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी निर्मला रावत को महज एक वोट से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली। इस नतीजे ने भाजपा के लिए बहुमत वाले जिले में भी सदस्यों को एकजुट रखने की चुनौती सामने रखी। आठ जिले ऐसे थे, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इन जिलों में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान समर्थन जुटाने और दूसरे दलों के सदस्यों को साथ लाने की रणनीति निर्णायक रही।

बालोतरा में भाजपा की सुशीला भील, डीडवाना-कुचामन में बुधाराम गरवा, डीग में रेनू सिंह, खैरथल-तिजारा में इंद्रजीत यादव और प्रतापगढ़ में हकरी कुमारी जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं। इस तरह भाजपा ने बिना स्पष्ट बहुमत वाले पांच जिलों में जीत हासिल की। वहीं, बांसवाड़ा में बीएपी की रीना और डूंगरपुर में बीएपी के अनुतोष रोत जिला प्रमुख बने। बांसवाड़ा में भाजपा के समर्थन से बीएपी प्रत्याशी की जीत ने आदिवासी अंचल में नए राजनीतिक समीकरणों को सामने ला दिया। सलूंबर में कांग्रेस की पुष्पा देवी ने जीत दर्ज की।

नागौर में आरएलपी के पांचाराम जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। यह जीत पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रही। पंचायत चुनाव में जिला परिषद स्तर पर सीमित मौजूदगी के बावजूद आरएलपी ने नागौर में जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ बनाए रखी।

राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा के अनुसार, पंचायत चुनाव के जिला प्रमुख नतीजों में कांग्रेस 24 जिलों के साथ सबसे आगे रही, जबकि भाजपा ने 10 जिलों में जिला प्रमुख बनाए। बीएपी को दो और आरएलपी को एक जिला मिला। कांग्रेस ने अपने स्पष्ट बहुमत वाले अधिकांश जिलों में जीत बरकरार रखी, लेकिन चूरू का नतीजा उसके लिए बड़ा झटका रहा।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने बहुमत वाले जिलों में भी जीत हासिल की और बिना बहुमत वाले पांच जिलों में जिला प्रमुख बनाकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। ब्यावर में बहुमत के बावजूद हार ने भाजपा के चुनावी प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। इन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया कि जिला परिषद सदस्य चुनाव के बाद जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए अलग राजनीतिक रणनीति और प्रबंधन की जरूरत होती है। केवल बहुमत के आंकड़े पर्याप्त नहीं होते, बल्कि मतदान के दिन सदस्यों की मौजूदगी, समर्थन और क्रॉस वोटिंग भी नतीजे तय करती है।

जनादेश का सम्मान, अगले दो साल राजस्थान की सेवा में लगाएंगे: राठौड़

जयपुर (कासं)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को जिला प्रमुख के चुनाव में 10 जिलों में पार्टी का जिला प्रमुख बनने पर जनता का आभार व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरी है, भाजपा लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए जनता के जनादेश को विनम्रता से ?स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में और अधिक गति से राजस्थान की सेवा की जाएगी और 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस को अपने उस झूठे प्रोपेगेंडा पर जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने परिसीमन पर झूठ बोला, ईवीएम



को बदनाम किया, हमारी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए गए। ये सब अब जनता के समझ में आ गया है, इसलिए कांग्रेस को जनता से और भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज के परिणाम विधानसभा के चुनाव परिणाम नहीं होते। अब तक हुए पंचायती राज चुनाव परिणामों के आधार पर भी ये बात साबित होती है कि पंचायती राज चुनावों में किसी पार्टी की जीत विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती है। राजस्थान की जनता ने पांच साल के लिए हमें जो सेवा का अवसर दिया है, उसी के अनुरूप अगले दो वर्ष हम पूरी प्रमाणिकता और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे।

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने भरतपुर चुनाव को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की थी, वह अराजकता को फैलाने वाली थी। यह जिम्मेदार राजनेता का बयान नहीं हो सकता। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह संयम का परिचय दिया उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कथनी और करनी में भेद है, चूरू में भाजपा की जीत पर कुछ कहते है और ब्यावर में कांग्रेस की जीत पर उनका बयान बदल जाता है।

सीबीएसई की तीन-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

तीन भाषा चुन चुके छात्रों को पुरानी व्यवस्था में पढ़ाई जारी रखने की छूट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीबीएसई की तीन-भाषा नीति के तहत पहले ही तीन भाषाएं चुन चुके छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उन्हें अब दो भाषाएं चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और सीबीएसई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति बागची ने



कहा, हमने कहा था कि कक्षा 6 के जिन छात्रों ने तीन भाषाएं चुनी हैं, वे तीन भाषाएं जारी रखेंगे। जिन्होंने तीन भाषाएं नहीं चुनी हैं, उन्हें इसके लिए मजबूर न करें, उन्हें उसी तरह पढ़ने दें, जैसे वे अभी पढ़ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जो छात्र अभी दो भाषाएं पढ़ रहे हैं, उन्हें इस साल दो भाषाएं जारी रखने की अनुमति होगी। यह बच्चों से जुड़ा मामला है। हम इसे यहां नहीं बढ़ाना चाहते। जिन्होंने पहले ही विकल्प चुन लिया है, वे जारी रखें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन छात्रों ने तीन भाषाएं चुनी हैं, उन्हें पुरानी व्यवस्था में लौटने की मांग नहीं करनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस बारे में स्पष्ट करेंगे।

सत्ता परिवर्तन वोटों से होता है, अराजकता से नहीं: राजनाथ सिंह

कलबुर्गी (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कलबुर्गी में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता मिटाओ' रैली में कहा कि वे कलबुर्गी संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर आए हैं। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों के जरिए नहीं, बल्कि हिंसा और अराजकता के रास्ते सत्ता में बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अराजकता से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हर जगह खारिज की जा रही है, जिसे राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सभी रणनीतियां विफल हो गई हैं, तो वे कह रहे हैं कि मोदी ऐसे नहीं जाएंगे और अब यहां सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अराजकता, अशांति और रक्तपात फैलाकर सरकार बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई पड़ोसी देशों में इस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्या कांग्रेस वैसी ही अराजकता फैलाकर यहां सरकार बनाना चाहती है? राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि सड़कों पर हंगामा करने से कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता केवल और केवल वोटों से बदलती है, अराजकता से नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सत्ता और कुर्सी की जिद में कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की गलतियों का जिक्र किया।

सपा की जल्दबाजी पर कांग्रेस नाराज, सीट बंटवारे में तीन डिजिट की रखी शर्त

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गुरूवार को लखनऊ में प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी को लेकर लखनऊ में जुटे पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर फायर हैं। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद के बाद अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का गुस्से वाला बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों की संख्या पर बात फाइनल होने से पहले ही सपा की उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने पर गौतम ने कहा कि सीटों की घोषणा कभी भी की जा सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मौजूदा परिस्थितियों में इससे बचना चाहिए था। उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी का गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए कहा कि जब दोनों दलों के बीच



बातचीत चल रही है, तो उम्मीदवारों की सूची क्यों जारी की गई। गौतम ने समाजवादी पार्टी की ओर से 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी किए जाने पर सवाल उठाए हैं।

गौतम ने कहा कि गठबंधन को लेकर 26 सीटों जैसी कोई बात नहीं है, दोनों दलों के बीच अभी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत अंतिम रूप लेने के बाद ही सभी को इसकी जानकारी देने की बात हुई थी, लेकिन मीडिया के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस को सिर्फ 26 सीट दी जा रही है।

कांग्रेस नेता ने गठबंधन को लेकर अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन यह सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तानाशाही नहीं चलती है। सीट के बंटवारे में सिर्फ तीन डिजिट में ही बात बनेगी।

दैनिक लोकजीवन
जयपुर एवं भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित
संस्थापक - स्व. रा. शिवकुमार जी तिवारी

संविधान की ताकत से सामान्य नागरिकों के सपनों को मिले पंख

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में, जहां अनेक पंथ हैं, भाषाएं हैं, रीति-रिवाज हैं, विचार परंपराएं हैं, वहां ये बहुत जरूरी है कि संविधान की गूंज संसद और अदालतों की चारदीवारी से कहीं आगे तक पहुंचे। हमारा प्रयास रहा है कि जन-जन की चेतना से, विशेषकर हमारे युवाओं से संविधान का जुड़ाव और गहरा हो। इससे राष्ट्रीय एकता की वो भावना और मजबूत होगी, जो भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ एक दशक पहले हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

हमारा संविधान मेरे साथ करोड़ों भारतीयों की जीवन यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। बचपन के वो साधारण हालात, जीवन के वो संघर्ष, जब भी मैं उस दौर को याद करता हूं, संविधान के प्रति मेरा हृदय अपार कृतज्ञता से भर जाता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बालक, जिसे विरासत में कोई विशेषाधिकार या सुविधा नहीं मिली, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेवा का दायित्व संभाल सकता है, ये हमारे संविधान की असाधारण शक्ति का प्रमाण है। ये हमारे संविधान की ही देन है कि आज किसी व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियां उसके भविष्य की सीमाएं तय नहीं करतीं।हमने अपने विनम्र प्रयासों से संविधान को और अधिक सशक्त बनाकर कृतज्ञता के इस ऋण को चुकाने की कोशिश की है।

प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने हमारे संविधान को 'प्रथमं सर्वप्रथमं सामाजिकदस्तावेजम्' बताया था। सामाजिक और आर्थिक न्याय की भावना हमारे संविधान के मूल में समाहित है। ऐसे में संविधान निर्माताओं के इस बहुमूल्य सपने को साकार करने के प्रयासों से अधिक संतोषजनक और क्या हो सकता है? विश्व बैंक की हाल में आई एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के करीब 50 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी से बाहर निकले हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे अभावों से मुक्ति पाकर आज करोड़ों माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने देख पा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से किसी परिवार को झोपड़ी से निकलकर पक्के मकान में गृह प्रवेश का अवसर मिलता है, तब गरिमापूर्ण जीवन जीने का संवैधानिक संकल्प सही मायनों में साकार होता है। जब उज्ज्वला योजना किसी मां को धुएं से भरी रसोई की तकलीफों से मुक्ति दिलाती है, तब हम समानता और जनकल्याण के आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं।

जब आयुष्मान भारत की वजह से किसी गरीब परिवार को कर्ज की चिंता किए बिना अच्छा इलाज मिलता है, तब उसके जीवन में सामाजिक न्याय का संकल्प साकार होता है। जब मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि के तहत छोटे उद्यमियों और रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के ऋण मिलता है, तब आर्थिक न्याय की संवैधानिक भावना जमीन पर उतरती है। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी, रूपे कार्ड और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म तक हर नागरिक की पहुंच होती है, तब समावेशिता का संवैधानिक आदर्श साकार होता है। पहले इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित कर दिया गया था।

संविधान की शक्ति से सामान्य मानवी को सशक्त बनाने के आज ऐसे कई और उदाहरण हैं। हमारी सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी जैसे बड़े सुधार का रास्ता खुला, जिसका लंबे समय से इंतजार था। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इससे समाज के वंचित वर्गों का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। हमारी सरकार द्वारा किए गए 103वें संविधान संशोधन को भी लोगों ने सराहा। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे लंबे समय तक आरक्षण व्यवस्था के दायरे से बाहर रहने वाले समुदायों को लाभ हुआ। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। 1950 के बाद पहली बार आज हमारे संविधान का अपडेटेड वर्जन आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। इससे हमारा संविधान जनसामान्य के और करीब आया है।

1950 में संविधान लागू होने के बाद भी हमारे देश में 1860 के दशक में, गुलामी के दौर में बनी दंड संहिता ही लागू रही। भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मंर मौलिक बदलाव लाने का प्रयास किया है। गुलामी के दौर की व्यवस्था में दंड पर जोर था। भारतीय न्याय संहिता का जोर नागरिक आधारित व्यवस्था और न्याय पर है। बीते एक दशक में हमने नागरिकों के कर्तव्यों पर विशेष बल दिया है। हमारी सभ्यता में समाज के हर व्यक्ति को उसकी भूमिका से जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोध कराने की परंपरा रही है। स्वच्छ भारत से लेकर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण तक, अनेक जन आंदोलनों में हमें कर्तव्य की इसी भावना के दर्शन हुए हैं। यहां मैं एक और सच्चाई देशवासियों के साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे इतिहास में ऐसे अवसर भी आए हैं, जब उन्हीं लोगों ने संविधान को कमजोर करने का रास्ता चुना, जिन पर इसकी रक्षा का दायित्व था।

स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी कोटा को बनाएंगे नम्बर 1 शहर: लोकसभा अध्यक्ष बिरला

जयपुर (कासं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा के खेल इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं विश्व स्तरीय एक्वाटिक सेंटर के निर्माण कार्य का शिलान्यास लाखों क्रिकेट प्रेमियों और खेल प्रतिभाओं के वर्षों पुराने सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हमारा संकल्प स्पोर्ट्स इन्फ्रा में कोटा को नम्बर 1 बनाना और कोटा-बूंदी को देश के प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। इसी दिशा में शहर से लेकर गांव तक खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। स्पीकर बिरला ने शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दो वर्षों में कोटा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में देश के अग्रणी शहरों में शामिल हो, इस लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं। 130 करोड़ की लागत से क्रिकेट स्टेडियम और एक्वाटिक सेंटर का निर्माण 2 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।

बिरला ने कहा कि अगले वर्ष कोटा में एयरपोर्ट का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। जनवरी 2028 में हवाई सेवाएँ प्रारंभ करने का लक्ष्य है। करीब 350 करोड़ रुपये से रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 1200 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण से महज 15 मिनट में दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे तक पहुंच सकेंगे। संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक गाँव और ढाणी को सड़क से जोड़ने का भी लक्ष्य है। बिरला ने कहा कि भामाशाह मंडी जल्द ही देश की प्रमुख मंडियों में शामिल होगी, इसके विस्तार का बरसों पुराना सपना शीघ्र पूरा होने जा रहा है। मंडी के विस्तार के लिए शीघ्र ही भूमि के फॉरेस्ट डायवर्जन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। अगले दो वर्षों में मंडी का व्यापक विस्तार कर किसानों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएँगी। हमारा प्रयास है कि मंडी को सीधे हाइवे और रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि देश भर तक हमारी पहुंच आसान हो सके।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा-बून्दी के विकास को नई गति देगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को डीसीएम रोड से जोड़ने की 1,600 करोड़ रुपए की परियोजना से एक्सप्रेस-वे तक पहुंचने का समय आधे घंटे से घटकर 15 मिनट रह जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। नहरों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बिरला की पहल से किसानों को लाभ मिला और धान की अच्छी पैदावार हुई। इससे बाजारों में रौनक लौटी है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि जेके पेवेलियन को करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा।

यहां दर्शकों के बैठने की व्यवस्था के साथ आधुनिक मैदान, पवेलियन, फ्लडलाइट, प्रसारण और अभ्यास सुविधाएं होंगी। इससे कोटा के युवाओं को यहीं प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तरणताल से तैराकी को भी बढ़ावा मिलेगा। मथुराधीश मंदिर



कॉरिडोर, मुकुंदरा, रामगढ़ अभयारण्य और एयरपोर्ट से पर्यटन बढ़ेगा। कोटा-बून्दी में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक कॉरिडोर के कार्य भी आगे बढ़ रहे हैं।

भावी पीढ़ियों को मिलेगा लाभ—

लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी ने कहा कि देश के खिलाड़ी जब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं तो पूरे देश का गौरव बढ़ता है। कोटा के बच्चों में भी ऐसी प्रतिभा है। जरूरत उन्हें उचित माहौल, प्रशिक्षण और अवसर देने की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और तरणताल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन सुविधाओं का लाभ केवल आज के खिलाड़ियों को ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। इससे कोटा के युवा अपने शहर में रहकर खेलों में आगे बढ़ सकेंगे और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, पंकज मेहता, पं. गोविंद शर्मा, महापौर श्रीमती अनुसुइया गोस्वामी, उप महापौर विवेक राजवंशी, केडीए आयुक्त बचनेश अग्रवाल, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव सत्यप्रकाश बालिता सहित अन्य पदाधिकारी गण एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी और गणमान्य मौजूद रहे।

वास्तुकला का होगा अद्भुत संगम—

क्रिकेट स्टेडियम केवल अपनी खेल सुविधाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्थापत्य और सुंदरता के लिए भी विशिष्ट पहचान बनाएगा। राजस्थान की सतरंगी संस्कृति और आधुनिक वास्तुकला का अद्भुत संगम इसमें देखने को मिलेगा। राजस्थानी स्थापत्य कला के मेहराब, छज्जे, झरोखे और रंग-बिरंगी पगड़ियों से प्रेरित स्टैंड की आकर्षक छतें इसकी भव्यता को बढ़ाएँगी। जब देश-दुनिया के खिलाड़ी यहाँ खेलने आएँगे, तो उन्हें आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होंगी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आधुनिक प्लेयर्स पवेलियन, ड्रेसिंग रूम, वीआईपी एवं कॉर्पोरेट बॉक्स, मीडिया गैलरी, टीवी प्रोडक्शन और अत्याधुनिक ब्रॉडकास्टिंग सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। बीसीसीआई के मानकों के अनुरूप क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया जाएगा। छह नई पिचें, खिलाड़ियों के लिए अलग प्रैक्टिस ग्राउंड, सिंथेटिक ट्रैक और रात्रिकालीन मुकाबलों के लिए चार विशाल फ्लड लाइट्स लगाई जाएँगी। खिलाड़ियों की आवश्यकताओं से लेकर दर्शकों की सुविधाओं तक, हर पहलू का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा एक्वाटिक सेंटर

क्रिकेट के साथ-साथ एथलेटिक के क्षेत्र में भी कोटा एक नई पहचान बनाने जा रहा है। अत्याधुनिक एक्वाटिक सेंटर में ओलंपिक मानकों के अनुरूप 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा ऑल वेदर कवर्ड स्विमिंग पूल विकसित किया जाएगा। यहाँ हमारे खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बिना वर्षभर अभ्यास कर सकेंगे। बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल, 300 से 400 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, आधुनिक जिम, एरोबिक्स, योग और बहुउद्देशीय हॉल सहित अनेक सुविधाएँ विकसित होंगी। इससे तैराकी के क्षेत्र में भी हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।

माइनिंग ब्लॉक्स के ऑक्शन में राजस्थान अव्वल, परिचालन में लाने पर फोकस, खान से जुड़े अन्तरविभागीय मुद्दों के निस्तारण पर जोर - मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खान विभाग द्वारा मेजर और माइनर ब्लॉकों के ऑक्शन में तेजी और नीलाम खानों को परिचालन में लाने के विभागीय प्रयासों की सराहना करते हुए अरावली जिलों को छोड़कर (नोन अरावली) अन्य स्थानों पर मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ब्लॉकों पर फोकस करने पर जोर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में ही अब तक 24 मेजर मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन कर राजस्थान समूचे देश में मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में अव्वल आ गया है। उन्होंने संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय व संवाद बनाकर अन्तरविभागीय मुद्दों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खनिज क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास बुधवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में खान विभाग के अंतरविभागीय प्रकरणों से जुड़ी वरिष्ठ अधिकारियों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सिया, वन, नगरीय विकास, राजस्व और परिवहन विभाग से माइंस विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नीलाम खानों को परिचालन में लाने में भी हमें समूचे देश में अग्रणी प्रदेश बनना है, इसके लिए आवश्यक अनुमतियां जारी करने और खनन कार्य आरंभ कराने के लिए संबंधित विभागों को एक्शन मोड़ पर आगे आना होगा।

श्रीनिवास ने जोधपुर शहर से जुड़े खनिज ब्लॉकों में खनन अनुमति के संबंध में अलग से बैठक करने के निर्देश दिये। साथ ही खान विभाग व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर खनन परिवहन में लगे वाहनों की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने सिया-सेक स्तर पर बकाया ईसी प्रकरणों के तेजी से निस्तारण को कहा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 55 मेजर मिनरल ब्लॉकों के साथ ही माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन का रोडमैप बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर खानधारकों व संबंधित विभागों के बीच समन्वय, सहयोग, मार्गदर्शन के लिए पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल बनाकर नियमित समीक्षा व समन्वय किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विभाग का फोकस अब नीलाम खानों को परिचालन में लाने पर है। एसीएस माइंस श्रीमती अरोरा ने बताया कि मेजर मिनरल खानों के परिचालन में तेजी लाई गई है, वहीं 716 माइनर मिनरल खानों को परिचालन में लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नीलाम खानों की पर्यावरण स्वीकृति के कार्य में तेजी आई पर अभी और तेजी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा सिया-सेक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय के समय ही संबंधित आवेदक खानधारकों को भी बुलाने से आवश्यक औपचारिकताओं में कमी होने पर तत्काल पूरा कराया जा सकता है। इससे स्वीकृति जारी करने में विलम्ब से बचा जा सकेगा।

श्रीमती अरोरा ने नगरीय विकास विभाग के जोधपुर, जयपुर-सांगानेर, कोटा आदि शहरी क्षेत्र से जुड़े माइनिंग ब्लॉकों में खनन स्वीकृति जारी करने पर जोर दिया ताकि इन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोका जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम बेशकीमती खनिज संपदा को कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे में खनिज चिन्हित क्षेत्रों पर वन, राजस्व, नगरीय विकास सहित संबंधित विभागों द्वारा परियोजना या अन्य निर्णय से पूर्व खान विभाग से समन्वय किया जाए। परिवहन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि अवैध खनन परिवहन में लिप्त चिन्हित वाहनों की सूचना विभाग द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है, उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध खनन परिवहन गतिविधियां करने वालों को सख्त संदेश दिया जा सके।

उन्होंने खनन परिवहन वाहनों से दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन वाहनों पर स्पीड़ गवर्नर लगवाने के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वन आनंद कुमार ने कहा कि एसीएस स्तर पर नियमित समीक्षा के साथ ही अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संबंधित को भी बुलाने के निर्देश दे दिए जाएंगे। इसी तरह से संरक्षण क्षेत्र घोषित करने संबंधी कार्रवाई से पहले खान विभाग से भी समन्वय बनाया जाएगा। एसीएस नगरीय विकास आलोक गुप्ता ने बताया कि बजरी से संबंधित प्रकरणों में अनुमति जारी कर दी गई है। वहीं अन्य मुद्दों पर भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

सचिव परिवहन पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार स्पीड गवर्नर के निर्देश जारी है और अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि खनिज परिवहन वाहनों पर कार्रवाई के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। बैठक में सिया अध्यक्ष मुनिश गर्ग, विशिष्ट सचिव माइंस श्रीमती नम्रता वृष्णि, सिया सचिव श्रीमती शैलजा देवल, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद, श्रीमती कोविता, उप सचिव राकेश कुमार, निदेशक माइंस एमपी मीणा, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, एसएमई जोधपुर देवेन्द्र गौड़, ओएसडी डॉ. अनुज सक्सेना, श्रीकृष्ण शर्मा, गृह, वन, राजस्व, परिवहन, खान तथा सिया के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

आयात पर निर्भरता अब भी बड़ी चुनौती, स्वदेशी की बढ़ती ताकत

- ललित शर्मा -

गौरतलब है कि पिछले दिनों बाजार में महंगाई की तमाम चुनौतियों के बावजूद स्थानीय और घरेलू उत्पादों की बिक्री की जबरदस्त रौनक उभरकर दिखाई दी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि विगत कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल का लगातार आह्वान नागरिकों के उपभोक्ता व्यवहार पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। परिणामस्वरूप, हर बीतते त्योहार के साथ भारतीय बाजारों में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग और बिक्री में सतत वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्तमान समय में जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की बाधाओं के कारण महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है, तब भी भारतीय उपभोक्ताओं के खरीददारी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस बार नवरात्रि से दिवाली तक करीब 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। वहीं, विभिन्न शीर्ष आर्थिक संस्थानों की रिपोर्टों के मुताबिक इस त्योहारी चक्र में भारत के कुल व्यापारिक कारोबार में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नि:संदेह, इस बार त्योहारी सीजन की सबसे सुखद तस्वीर यह रही कि भारतीय बाजारों में चीनी उत्पादों का वर्चस्व तेजी से घटा है और स्वदेशी सामानों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि हम एक दशक पूर्व की स्थिति का स्मरण करें, तो दिवाली के बाजारों पर सस्ते, आकर्षक, लेकिन घटिया गुणवत्ता वाले चीनी सामानों का 70 से 80 प्रतिशत तक एकछत्र राज हुआ करता था। चाहे सजावटी एलईडी लाइटें हों, प्लास्टिक के उपहार, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, आतिशबाजी हो या फिर बच्चों के खिलौने, चीन से बड़े पैमाने पर होने वाले आयात ने भारत के पारंपरिक कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों और लघु उद्यमियों को गंभीर रूप से हाशिए पर धकेल दिया था।

इसके साथ ही, देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हर वर्ष पानी की तरह बाहर चली जाती थी। यद्यपि भारत के कुल आयात और व्यापार घाटे में चीन का हिस्सा अब भी बड़ा है, लेकिन त्योहारी और उपभोग योग्य सामानों के आयात में आई यह भारी कमी एक बहुत बड़ा सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक बदलाव है। भारतीय उपभोक्ता अब चीनी सामानों के स्थान पर विशुद्ध रूप से स्वदेशी, प्राकृतिक और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। इस बड़े बदलाव के कारण भारत को त्योहारी मौसम के दौरान अरबों रुपए की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक बचत करने में बड़ी सफलता मिली है। भारतीय कारीगरों और 'मेक इन इंडिया' का सशक्तिकरण यह महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन केवल किसी भावुक अपील का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीय कारीगरों, बुनकरों, लघु उद्यमियों और 'मेक इन इंडिया' समूहों की कड़ी मेहनत, नवाचार और तकनीकी सुधार का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र ने तकनीक, डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और सप्लाई चेन के मोर्चे पर खुद को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बना लिया है। ऐसे चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य में देश के प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाना केवल खरीदारी का विकल्प नहीं, बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में भागीदारी का माध्यम है। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन, पैकेजिंग और विपणन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाए। छोटे उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, आसान ऋण और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी विशेष ध्यान देना होगा। सरकार के साथ निजी क्षेत्र और उपभोक्ताओं को भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। स्थानीय उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स के माध्यम से देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने से नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पारंपरिक हुनर को भी नई पहचान मिलेगी। साथ ही, आयात के विकल्प के रूप में मजबूत घरेलू उत्पादन तंत्र विकसित करना समय की आवश्यकता है। हालांकि, इसका अर्थ वैश्विक व्यापार से दूरी बनाना नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करना है।

भारत को ऐसी आर्थिक व्यवस्था विकसित करनी होगी, जहां घरेलू मांग का बड़ा हिस्सा देश में निर्मित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से पूरा हो। यही स्वदेशी सोच को आर्थिक शक्ति में बदलने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को वास्तविक धरातल पर उतारने का प्रभावी रास्ता है। इसके साथ ही देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना भी आवश्यक है, ताकि भारतीय उद्योग केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित न रहें, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकें। कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, खिलौना निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि इन क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक और पर्याप्त निवेश का सहयोग मिले तो लाखों नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को स्थानीय उत्पादन से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। इसके लिए जिला स्तर पर छोटे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग की रणनीति अपनानी होगी। साथ ही, भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग और गुणवत्ता प्रमाणन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना होगा। उपभोक्ताओं के बीच यह विश्वास पैदा करना जरूरी है कि स्वदेशी उत्पाद गुणवत्ता और टिकाऊपन के मामले में किसी भी विदेशी ब्रांड से कम नहीं हैं। दूसरी ओर, अनावश्यक आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जहां देश के भीतर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। वास्तव में, स्वदेशी अभियान तभी व्यापक आर्थिक बदलाव का आधार बनेगा, जब उत्पादन, रोजगार, निवेश और उपभोग के बीच मजबूत संबंध स्थापित होंगे। देश की आर्थिक मजबूती का रास्ता स्थानीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने से होकर गुजरता है।

आज के देशी उत्पाद न केवल उच्च स्तर पर टिकाऊ हैं, बल्कि आधुनिक उपभोक्ता की पसंद, सौंदर्यबोध और उपयोगिता पर भी पूरी तरह खरे उतर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, जब कोई भी नागरिक किसी विदेशी कंपनी के बजाय स्थानीय उत्पाद खरीदता है, तो उसकी गाढ़ी कमाई का सीधा लाभ किसी विदेशी बाजार में जाने के बजाय भारत की जड़ों में बसे छोटे कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, हस्तशिल्पियों और महिला स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचता है। इससे धन का न्यायसंगत पुनर्वितरण होता है और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्थाएं भीतर से मजबूत होती हैं।

निश्चित रूप से, पिछले एक दशक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने दूरदर्शी अभियानों के जरिए ग्रामीण शिल्पकारों को निरंतर सशक्त बनाया है। ग्रामोद्योग विकास योजना और कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत देशभर में हजारों कुम्हारों को आधुनिक इलेक्ट्रिक चाक और उन्नत टूलकिट वितरित किए गए हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में 3 से 4 गुना की भारी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केवीआईसी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो बढक़र 2025-26 में 1.87 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया। आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2.51 लाख करोड़ रुपए के विशाल कारोबार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के कुल उत्पादन में लगभग 320 प्रतिशत और बिक्री में 400 प्रतिशत से अधिक की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। स्थानीय उत्पादों का यह प्रोत्साहन केवल मिट्टी के पारंपरिक दीयों या हस्तशिल्प तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी इसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के योजनाबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के नए क्लस्टर स्थापित हुए हैं। इन स्वदेशी निर्माण इकाइयों और एमएसएमई इलेक्ट्रॉनिक्स समूहों ने इस वर्ष भारत के त्योहारी बाजार की करीब 80 प्रतिशत से अधिक प्रकाश व्यवस्था, सजावटी लडिय़ों और गृह-सज्जा उत्पादों की मांग को स्वदेशी उत्पादन के बल पर सफलतापूर्वक पूरा किया है। जिन सजावटी लाइटों के लिए भारत कभी बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर हुआ करता था, आज वे उत्पाद उच्च गुणवत्ता और बेहद किफायती दरों पर भारत की अपनी धरती पर ही निर्मित हो रहे हैं।

बहरहाल, अब स्थानीय उत्पादों का मजबूत बाजार विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। निश्चित रूप से, जहां एक ओर देश के त्योहारी बाजार में त्योहार से जुड़े स्थानीय और घरेलू उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर चीन से आयातित त्योहारी उत्पादों की मांग में लगातार कमी आ रही है। इस सुकूनदायक परिदृश्य के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चीन सहित अन्य देशों से त्योहारी उत्पादों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और अन्य उत्पादों का आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में, स्वदेशी और घरेलू उत्पादों की नियमित मांग को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ाकर आयात पर नियंत्रण करना होगा, ताकि व्यापार घाटे को काबू में रखते हुए रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ा जा सके। उल्लेखनीय है कि हाल ही में 13 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तु व्यापार (मरचेंडाइज ट्रेड) घाटा बढक़र 39.88 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले 12 महीनों का सबसे उच्च स्तर है। कच्चे तेल के बढ़ते आयात, इलेक्ट्रॉनिक सहित विभिन्न वस्तुओं के बढ़ते आयात और सोने की खरीददारी में आई भारी तेजी के कारण आयात में यह उछाल देखने को मिला है।

बदलती लाइफस्टाइल से हो सकता है स्तन कैंसर, ऐसे करें बचाव

भारत में महिलाओं में कैंसर के मामलों में 27 प्रतिशत मामले स्तन कैंसर के हैं। इस तरह की परेशानी 30 वर्ष की उम्र के शुरुआती वर्षों में होती है, जो आगे चलकर 50 से 64 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। स्तन कैंसर के कुछ लक्षणों में स्तन या बगल में गांठ बन जाना, स्तन के निप्पल से खून आना, स्तन की त्वचा पर नारंगी धब्बे पड़ना, स्तन में दर्द होना, गले या बगल में लिम्फ नोड्स के कारण सूजन होना आदि प्रमुख हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 28 में से किसी एक महिला को जीवनकाल में कभी न कभी स्तन कैंसर होने का अंदेशा रहता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के मुताबिक, भारतीय महिलाओं में छोटी उम्र में ही स्तन कैंसर होने लगा है। जागरूकता की कमी और रोग की पहचान में देरी के चलते उपचार में कठिनाई भी आती है।

स्तन कैंसर में इस रोग के ऊतक या टिश्यू स्तन के अंदर विकसित होते हैं। इस रोग होने के पीछे जो कारक हैं, उनमें प्रमुख हैं- जीन की बनावट, पर्यावरण और दोषपूर्ण



जीवनशैली। बचाव के लिए जरूरी है कि 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जाए। साथ ही जीवनशैली में भी कुछ बदलाव किए जाएं तो इस रोग की आशंका कम की जा सकती है।

उच्च वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है स्तन कैंसर का खतरा

आईएमए के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ। के।के। अग्रवाल ने कहा, यह ज्ञात हो चुका है कि डीएनए में अचानक से होने वाले परिवर्तनों के कारण सामान्य स्तन कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है। यद्यपि इनमें से कुछ परिवर्तन तो माता-पिता से मिलते हैं, लेकिन बाकी ऐसे परिवर्तन जीवन में खुद ही प्राप्त होते हैं। प्रोटोओंकोजीन्स की मदद से ये कोशिकाएं बढ़ती ताजी हैं। जब इन कोशिकाओं में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है, तब ये कैंसर कोशिकाएं बेरोकटोक बढ़ती जाती हैं।

ऐसे उत्परिवर्तन को ओंकोजीन के रूप में जाना जाता है। एक अनियंत्रित कोशिका वृद्धि कैंसर का कारण बन सकती है। बीआरसीए1 और बीआरसीए2 जीन में उत्परिवर्तन होते हैं। माता-पिता से उत्परिवर्तित जीन से स्तन कैंसर का जोखिम अधिक होता है। उच्च जोखिम वाली महिलाओं को हर साल एमआरआई और मैमोग्राम कराना चाहिए।

'हॉर्मोनल गर्भनिरोधक से बढ़ता है स्तन कैंसर का खतरा'

डॉ. अग्रवाल ने कहा, एस्ट्रोजेन स्तन ग्रंथियों के ऊतकों के विभाजन को तीव्र करता है। किसी महिला में यदि लंबे समय तक एस्ट्रोजेन अधिक रहता है, तो स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा रहता है। यदि 11 वर्ष की आयु या उससे पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाए या 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में रजोनिवृत्ति हो तो माना जाता है कि एस्ट्रोजेन का एक्सपोजर अधिक है। महिलाओं को 45 वर्ष से 54 वर्ष की उम्र तक हर साल एक बार स्क्रीनिंग मैमोग्राम करा लेना चाहिए। 55 वर्ष या अधिक उम्र की महिलाओं को सालाना स्क्रीनिंग करानी चाहिए।

स्तन कैंसर से बचाव के कुछ उपाय

शराब का सेवन कम करें

शराब से स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आदी हों तो दिन में एक पैग से अधिक न लें, क्योंकि शराब की कम मात्रा से भी खतरा रहता है।

धूम्रपान से बचें

अनुसंधान बताता है कि धूम्रपान और स्तन कैंसर के बीच एक संबंध है। इसलिए, यह आदत छोड़ने में ही भलाई है।

शरीर का वजन काबू में रखें

सक्रिय जीवन जीएं। अधिक वजन या मोटापे से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। रोजाना लगभग 30 मिनट व्यायाम अवश्य करें।

स्तनपान

स्तनपान कराने से स्तन कैंसर की रोकथाम होती है।

हार्मोन थेरेपी को कम करें

हार्मोन थेरेपी की अवधि तीन से पांच साल तक होने पर स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सबसे कम खुराक का प्रयोग करें जो आपके लिए प्रभावी है। आप कितना हारमोन लेते हैं इसकी निगरानी डॉक्टर खुद करे तो बेहतर होगा।

स्वस्थ आहार लें

फलों और सब्जियों से समृद्ध, संपूर्ण अनाज और कम वसा वाला आहार लें।

तनाव से बचें

यह प्रतिरक्षा को कमजोर करता है और शरीर के रक्षा तंत्र को बिगाड़ता है। योग अभ्यास, गहरी सांस लेने और व्यायामक रने से लाभ होता है।

बच्चों में तनाव के कारण होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर

अध्ययनों के अनुसार, भारत में लगभग 1.6 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत तक बच्चों में एडीएचडी की समस्या पाई जाती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर अथवा ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी को एडीएचडी कहा जाता है. एडीएचडी की समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहां घर में तनाव का वातावरण रहता है और जहां पढ़ाई पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति रहती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के मुताबिक, एडीएचडी की समस्या ज्यादातर प्री-स्कूल या केजी कक्षाओं के बच्चों में होती है। कुछ बच्चों में, किशोरावस्था की शुरुआत में स्थिति खराब हो सकती है। यह वयस्कों में भी हो सकता है।

आईएमए के अध्यक्ष डॉ. के.के. अग्रवाल ने कहा, एडीएचडी वाले बच्चे बेहद सक्रिय और कुछ अन्य व्यवहारगत समस्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं। उनकी देखभाल करना और उन्हें कुछ सिखाना मुश्किल हो जाता है। वे स्कूल में भी जल्दी फिट नहीं हो पाते हैं और कोई न कोई शरारत करते रहते हैं। यदि इस कंडीशन को शुरू में ही काबू न किया जाए तो यह जीवन में



बाद में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा, यद्यपि, एडीएचडी का कोई इलाज नहीं है, परंतु उपचार के लक्षणों को कम करने और ऐसे बच्चों की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय किए जा सकते हैं। कुछ उपचार विकल्पों में दवाएं, मनोचिकित्सा, शिक्षा या प्रशिक्षण या इनका मिश्रण शामिल है। एडीएचडी के लक्षणों को अक्सर तीन श्रेणियों में बांटा जाता है - ध्यान न देना, जरूरत से अधिक सक्रियता और असंतोष। चीनी, टीवी देखने, गरीबी या फूड एलर्जी से एडीएचडी नहीं होता। डॉ। अग्रवाल ने बताया, शिक्षा, समर्थन और रचनात्मकता से ऐसे बच्चों में इस स्थिति का प्रबंधन करने में काफी मदद मिल सकती है। यद्यपि एडीएचडी वाले बच्चों के साथ ठीक से रह पाना एक चुनौती है, लेकिन समय को प्राथमिकता देने और हर चीज टाइम टेबल के हिसाब से करने पर मदद मिल सकती है। माता-पिता को यह याद रखना चाहिए कि एडीएचडी से आपके बच्चे की बुद्धि या क्षमता का पता नहीं चल पाता है। बच्चे की शक्तियों का पता लगाएं और बेहतर परिणामों के लिए उन शक्तियों पर ध्यान दें।

एडीएचडी वाले बच्चों का प्रबंधन करने के उपाय

रूटीन सेट करें : स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, ताकि हर कोई जान ले कि किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है।

पुरस्कार और इनाम : अच्छे काम पर प्रशंसा या पुरस्कार देने से सकारात्मक व्यवहार को मजबूत किया जा सकता है। अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए आप अंक या स्टार सिस्टम का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं।

चेतावनी के संकेतों पर ध्यान दें : यदि ऐसा दिखे कि बच्चा आपा खो रहा है, तो उस पर ध्यान दें और उसे किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त कर दें।

मित्रों को आमंत्रित करें : इससे बच्चे को मिलने-जुलने में आसानी होगी। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि बच्चा स्वयं पर नियंत्रण न खोए।

नींद में सुधार करें : अपने बच्चे को अच्छी नींद सोने दें। सोने के समय उसे किसी रोमांचक गतिविधि में न उलझने दें।

हेल्दी लाइफस्टाइल से बुढ़ापे में भी दिमाग बनेगा स्मार्ट

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) के एक नए परामर्श के मुताबिक, यदि आप अपने आने वाले वर्षों में भी स्मार्ट रहना चाहते हैं? तो आपको बचपन से ही एक स्वस्थ जीवनशैली बनानी होगी, क्योंकि यह उम्र में एक संज्ञानात्मक गिरावट के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल और रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि बड़े और छोटे रक्त कणों को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें संकुचित बनाते हुए जाम कर सकती है। इसे एथरोस्क्लेरोसिस नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बीमारी की प्रक्रिया है, जो कई दिल के दौरों और स्ट्रोक का प्रमुख कारण है। अध्ययन में पता चला है कि यदि मौजूदा चलन कायम रहता है तो दुनिया भर में 7.50 लोग पागलपन के शिकार हो सकते हैं।

मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप गोरलिक



ने कहा कि अध्ययन, आश्वस्त रूप से यह दर्शाता है कि एक ही जोखिम वाले कारक एथरोस्क्लेरोसिस का कारण बनते हैं और साथ ही अधिक उम्र में संज्ञानात्मक हानि और अल्जाइमर रोग में भी योगदान करते हैं।

स्वास्थ्य कारक, जिसे जीवन का सरल 7 कार्यक्रम कहा जाता है। ये लोगों के रक्तचाप को प्रबंधित करने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, रक्त शर्करा को सामान्य रखने, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने, स्वस्थ आहार लेने, अतिरिक्त वजन घटाने, धूम्रपान न करने या छोड़ने का आग्रह करते हैं।

मिशिगन के मर्सी हेल्थ ह्यूनस्टीन न्यूरोसाइंसेस में वैस्कुलर न्यूरोलॉजिस्ट और चिकित्सा निदेशक, गॉर्लिकिक ने कहा है, जीवन के सरल 7 का अनुसरण करके हम न केवल दिल के दौरों और स्ट्रोक को रोक सकते हैं, बल्कि हम संज्ञानात्मक हानि को रोकने में भी सक्षम हो सकते हैं।

यह परामर्श 182 प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनों और स्ट्रोक नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर दी गई है, और आपके मस्तिष्क को यथासंभव स्वस्थ रखने के लिए कदम उठाने के महत्व पर बल देती है, क्योंकि एथ्रोरोस्लेरोसिस बचपन में ही शुरू हो जाता है।

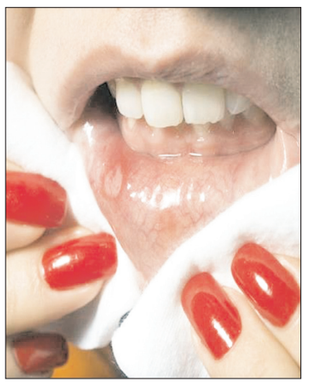

मुंह के छालों को एक दिन में ही ठीक करेंगे ये पक्के नुस्खे

मुंह में छाले होना एक आम समस्या है। पेट में गड़बड़ी या पाचन शक्ति ठीक न होने की वजह से यह समस्या हो जाती है। इसके अलावा अधिक मसालेदार भोजन करने के कारण भी मुंह में छाले हो जाते हैं। ये जीभ पर या होंठों के बीच कहीं भी हो सकते हैं और कुछ भी खाने-पीने पर मुंह में बहुत तेज दर्द व जलन महसूस होती है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय करके मुंह के छालों से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानिए ऐसे ही कुछ आसान तरीकों के बारे में।



मुलेठी

मुंह में छाले होने पर मुलेठी बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसके लिए 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को 2 कप पानी में डालकर 3-4 घंटों के लिए रख दें और फिर इस पानी से दिन में 4-5 बार कुल्ला करें। इस प्रक्रिया से 1 दिन में ही छालों से राहत मिलेगी।

नारियल का दूध

इसके लिए 1 चम्मच नारियल दूध में थोड़ा-सा शहद मिलाकर छालों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से दर्द से भी राहत मिलेगी और छाले भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा नारियल के दूध को 10-15 मिनट के लिए मुंह में रखने से भी छालों से राहत मिलती है।

धनिए की बीज

सभी घरों में धनिए के बीज तो आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें मुंह के छालों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 1 चम्मच धनिए के बीजों को 1 कप पानी में उबाल लें और छान कर ठंडा होने के लिए रख दें। इस पानी से दिन में 2-3 बार कुल्ला करने से छाले ठीक हो जाते हैं।

बेकिंग सोडा

इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो छालों को ठीक करने में मदद करता है। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडे में पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को छालों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करने से छालों में आराम मिलता है।

शहद

छालों पर शहद लगाने से भी दर्द और जलन से राहत मिलती है। इसके अलावा नींबू के रस में शहद मिलाकर इससे कुल्ला करने से भी छाले ठीक हो जाते हैं।



25 मिनट के इस योग से दिमाग होगा दुरुस्त और बढ़ जाएगा एनर्जी लेवल

केवल 25 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन के साथ रोजाना हठ योग (आसन, प्राणायाम और ध्यान का एक संयोजन) करने से मस्तिष्क तंत्र के क्रियान्वयन व ऊर्जा स्तर में काफी सुधार हो सकता है। एक शोध में पता चला है कि नियमित तौर पर हठ योग और माइंडफुलनेस मेडिटेशन (ध्यान की एक स्थिति) मस्तिष्क तंत्र के क्रियान्वयन, लक्ष्य-निर्देशित व्यवहार से जुड़ी संज्ञानात्मक व भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमताओं, स्वाभाविक सोच की प्रक्रियाएं और क्रियाएं को बढ़ावा दे सकता है।

कनाडा की ओंटारियो स्थिति यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में सहायक प्राध्यापक पीटर हॉल ने कहा, हठ योग और माइंडफुलनेस मेडिटेशन दोनों ही ध्यान सत्र के बाद कुछ सकारात्मक प्रभाव देते हैं जिससे लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में करना चाहते हैं उस पर अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

हठ योग पश्चिमी देशों में प्रचलित योगों की सबसे आम शैलियों में से एक है, जिसमें ध्यान को शारीरिक आसनों और सांस लेने के व्यायाम से जोड़ा जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में विचारों, भावनाओं और शरीर की उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और हठ योग दोनों ऊर्जा स्तर में सुधार के लिए प्रभावी पाए गए हैं, लेकिन केवल ध्यान करने की तुलना में हठ योग व ध्यान दोनों एक साथ में काफी अधिक शक्तिशाली प्रभाव देते हैं।

गर्भावस्था के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के दिमाग को प्रभावित नहीं करता : अध्ययन

गर्भावस्था के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। यह विकास बच्चे में भाषा और उसकी हाथ पैर चलाने की क्षमता से जुड़ा है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। नार्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के यहां पैदा हुए बच्चों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने वाली माताओं के बच्चों की तुलना में वाक्य जटिलता होने का जोखिम 27 प्रतिशत कम होता है, अपूर्ण व्याकरण की दृष्टि से 14 प्रतिशत कम और तीन वर्ष की उम्र में मध्यम भाषा के ज्ञान की दृष्टि से 31 प्रतिशत कम



था। अध्ययन में यह भी पाया गया कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाली माताओं के यहां जन्मे बच्चों में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने वाली माताओं के यहां जन्में बच्चों की तुलना में तीन वर्ष की उम्र में मोटर कौशल का खतरा 18 प्रतिशत कम था।

अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, हमारा अध्ययन गर्भावस्था के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल के कारण बच्चों की भाषा,संचार और मोटर कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव की कल्पना का समर्थन नहीं करता।% नार्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के जान अलेक्जेंडर ने कहा, %हमारा अध्ययन यह सबूत उपलब्ध कराता है कि गर्भवती महिला द्वारा सेल फोन का इस्तेमाल भ्रूण के न्यूरो विकास पर नुकसान पहुंचाने के जोखिम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अध्ययन के लिए 45,389 मां-बच्चे के जोड़ों को शामिल किया गया। यह अध्ययन जर्नल बीएमसी पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ है।

बच्चों के गले के बैक्टीरिया हो सकते हैं जोड़ों में संक्रमण का संकेत



वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों के गले में किसी खास बैक्टीरिया की मौजूदगी हड्डी और जोड़ों के संक्रमण का संकेत दे सकती है। इस बैक्टीरिया के कारण बच्चों के चलने-फिरने पर तो बुरा प्रभाव पड़ ही सकता है, साथ ही साथ मौत का खतरा भी हो सकता है। एक नए अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि बच्चों के गले में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किंगेला किंगे इसी बैक्टीरिया के कारण होने वाले हड्डियों एवं जोड़ों के संक्रमण से जुड़ा है। इससे पहले माना जाता था कि अधिकतर संक्रमण स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और हेमोफीलस इंफ्लूएंजा टाइप बी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तब इनका इलाज लंबे समय तक चलने वाले एंटीबायोटिक और या सर्जरी से किया जाता था। पिछले कुछ साल में बेहद संवेदनशील तकनीकों के कारण इन संक्रमणों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की सटीक पहचान संभव हो सकी। शोधकर्ताओं ने छह माह से चार साल तक के 77 बच्चों का अध्ययन किया। इन्हें हड्डी या जोड़ संक्रमण के संदेह के चलते भर्ती कराया गया था। इनमें से 65 बच्चों को पक्के तौर पर हड्डी या जोड़ों का संक्रमण था।उन्होंने पाया कि चार साल से कम उम्र के जिन बच्चों में हड्डी या जोड़ों का संक्रमण पाया गया था, उनमें से अधिकतर बच्चे किंगेला किंगे बैक्टीरिया से संक्रमित थे। कनाडा के मोंट्रियल विश्वविद्यालय के जोसलेन ग्रेवल ने कहा, ''सबसे अहम बात यह है कि हमने यह पता लगाया क जिन बच्चों को हड्डी या जोड़ों का संक्रमण था, उनके गले में ये बैक्टीरिया मौजूद थे। हालांकि संक्रमण से बचे हुए बच्चों ञात्र छह प्रतिशत- में यह बात सामान्य नहीं है।''

देश-विदेश में बढ़ा राजस्थान फाउंडेशन का दायरा, अब 51 चैप्टर

❐ वर्ष 2023 में थे केवल 12 चैप्टर, पिछले तीन वर्षों में 39 नए बनाए

❐ अब न्यूयॉर्क से ऑकलैंड और दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक फैला प्रवासी राजस्थानी चैप्टर नेटवर्क

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए पिछले 3 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में प्रवासियों के लिए नए विभाग का गठन, राजस्थान फाउंडेशन द्वारा नए चैप्टर का गठन, जिलों में प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन, प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासियों के साथ निरंतर संवाद, देश-विदेश में प्रवासी मीट सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

राजस्थान फाउंडेशन का नेटवर्क अब 51 चैप्टर तक विस्तारित हो गया है। इनमें 25 राष्ट्रीय और 26 अंतरराष्ट्रीय चैप्टर शामिल हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान फाउंडेशन के केवल 12 चैप्टर थे, जो भी क्रियाशील नहीं थे। इन सभी को क्रियाशील करने के साथ ही पिछले तीन वर्षों में 39 नए चैप्टर बनाए गए हैं।

28 नए चैप्टर गठित, 11 के गठन की प्रक्रिया शुरू

राजस्थान फाउंडेशन द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए नए चैप्टर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 अक्टूबर, 2026 को प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम के दौरान 11 नए चैप्टर गठित



करने की घोषणा की थी। इन सभी चैप्टर के गठन तथा अध्यक्षों के मनोनयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 के अवसर पर 14 नए चैप्टर गठित करने की घोषणा की थी। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा अब इन सभी 14 चैप्टर का गठन कर इन्हें क्रियाशील कर दिया गया है। इनमें 9 अंतरराष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय चैप्टर शामिल हैं। साथ ही, 14 नए चैप्टर्स का पूर्व में ही गठन किया जा चुका है।

राजस्थान फाउंडेशन के इस विस्तार से विश्वभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद, समन्वय और सहभागिता को नई गति मिलेगी। इससे प्रवासी समुदाय को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और निवेश संबंधी विकास कार्यों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। इन चैप्टर के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के बीच मजबूत नेटवर्क विकसित होगा। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान, निवेश प्रोत्साहन, कौशल एवं तकनीकी सहयोग, शिक्षा, पर्यटन तथा समाजसेवा के क्षेत्रों में नई संभावनाओं का विस्तार होगा।

26 अंतरराष्ट्रीय चैप्टर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), मनामा (बहरीन), कुवैत सिटी (कुवैत), मस्कट (ओमान), कुआलालंपुर (मलेशिया), बैंकॉक (थाईलैंड), हांगकांग, ऑकलैंड (न्यूजीलैंड), टोरंटो (कनाडा), दुबई (संयुक्त अरब अमीरात), दोहा (कतर), रियाद (सऊदी अरब), लंदन (यूनाइटेड किंगडम), न्यूयॉर्क (अमेरिका), सिंगापुर, टोक्यो (जापान), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), काठमांडू (नेपाल), कंपाला (युगांडा), म्यूनिख (जर्मनी) और नैरोबी (केन्या) में चैप्टर क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका), ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड), मिलान (इटली), डबलिन (आयरलैंड) और नॉर्डिक (स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड) में नए चैप्टर्स की घोषणा की जा चुकी है।

25 राष्ट्रीय चैप्टर

देश में फरीदाबाद (हरियाणा), तिरुवनंतपुरम (केरल), लुधियाना (पंजाब), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और गंगटोक (सिक्किम), मुंबई (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात), सूरत (गुजरात), इंदौर (मध्य प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), दिल्ली, रांची (झारखंड), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), बेंगलुरु (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), कोयंबटूर (तमिलनाडु), भुवनेश्वर (ओडिशा) और गुवाहाटी (असम) में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर संचालित हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर (छत्तीसगढ़) , लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल), पणजी (गोवा) और विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में नए चैप्टर्स की घोषणा की जा चुकी है।

दूसरा प्रवासी राजस्थानी दिवस: 8 से 10 दिसम्बर तक भव्य आयोजन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में 10 दिसम्बर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस क्रम में दूसरा प्रवासी दिवस आगामी 10 दिसम्बर आयोजित किया जा रहा है।

इसके तहत 8 दिसम्बर को झुंझुनूं के खेतड़ी स्थित अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट और 9 दिसम्बर को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रवासी सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा।

न्यूज इनबॉक्स

साबरमती-हरिद्वार-साबरमती स्पेशल रेलसेवा की संचालन अवधि में विस्तार

जयपुर (कासं)। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु साबरमती-हरिद्वार-साबरमती स्पेशल रेलसेवा की संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 09425/09426, साबरमती-हरिद्वार-साबरमती स्पेशल रेलसेवा की संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत गाड़ी संख्या 09425 साबरमती-हरिद्वार स्पेशल रेलसेवा साबरमती से दिनांक 30.11.2026 से 07.12.2026 तक (02 ट्रिप) तथा गाड़ी संख्या 09426 हरिद्वार-साबरमती स्पेशल रेलसेवा हरिद्वार से दिनांक 01.12.2026 से 08.12.2026 तक (02 ट्रिप) संचालित की जाएगी। उपरोक्त रेलसेवा का संचालन समय एवं ठहराव यथावत रहेंगे।

राज्यपाल बागडे से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मुलाकात की

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से बुधवार को लोकभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

स्पीकर देवनानी से मुख्य सचिव की मुलाकात

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से बुधवार को यहां विधान सभा में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्य सचिव ने स्पीकर देवनानी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया।

संविधान दिवस पर राज्यपाल बागडे की बधाई और शुभकामनाएं

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्वभर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। राज्यपाल बागडे ने संविधान दिवस (26 नवम्बर) की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि संविधान की उद्देशिका 'हम भारत के लोग' देश में संप्रभुता और लोकतांत्रिक भारतीय मूल्यों का ही दर्शन है। संविधान की आस्था 'लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति' में है। उन्होंने कहा कि संविधान का मूल भाव मानवता है। नागरिकों में बंधुता, स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हमारा संविधान देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का घोषणा पत्र है। राज्यपाल ने कहा कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए अपने पहले भाषण में 'संवैधानिक नैतिकता' शब्द का प्रयोग किया था। यही हमारे गणतंत्र की पहचान है। उन्होंने संविधान दिवस पर संविधान से जुड़ी संस्कृति और इससे जुड़े अधिकारों के प्रति सजग रहते सभी को कर्तव्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया है।

हमारा संविधान ही हमारा पथप्रदर्शक और नैतिक संबल है- देवनानी

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। देवनानी ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे राष्ट्र का संविधान, इसके निर्माताओं की दूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण है। यह संविधान सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की जटिलताओं और चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र का मार्ग दर्शन करने में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। देवनानी ने कहा कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति उसकी संस्थाओं की मर्यादा, विधि के शासन और नागरिकों के संवैधानिक आचरण में निहित होती है। उन्होंने कहा कि विधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते वे यह अनुभव करते हैं कि सदन की कार्यवाही से लेकर जनकल्याण की प्रत्येक नीति तक, हमारा संविधान ही हमारा पथप्रदर्शक और नैतिक संबल है। देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जन-प्रतिनिधियों के दायित्वों का निर्वहन करते हुए यह निरंतर अनुभूति होती है कि हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि कितनी विलक्षण थी। उन्होंने हमें एक ऐसी शासन प्रणाली दी है, जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने निर्धारित दायरे में रहते हुए राष्ट्र निर्माण के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। संविधान केवल अधिकारों का घोषणा-पत्र नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक को उसके कर्तव्यों का बोध भी कराता है।

देवनानी ने कहा कि उनका यह सदैव प्रयास रहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और संविधान के मूल आदर्शों से आमजन, विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी और युवा वर्ग, सीधे तौर पर परिचित हो सकें। इसी विचार को मूर्त रूप देते हुए राजस्थान विधान सभा के संग्रहालय में 'संविधान दीर्घा' का निर्माण कराया गया है। यह दीर्घा केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों और कलाकृतियों का प्रदर्शन मात्र नहीं है, अपितु यह भावी पीढ़ी को हमारे लोकतांत्रिक संस्कारों और राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने का एक विनम्र उपक्रम है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का लोकतन्त्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बडा लिखित संविधान हैं। समस्त लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थायें अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करती हैं। संविधान किसी भी प्रकार की अराजकता, स्वच्छन्दता और अमर्यादित आचरण की अनुमति नहीं देता है। अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति पूर्ण जागरूक रहते हुए 'विकसित भारत निर्माण' के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

नैनो यूरिया, एसएसपी एवं एनपीके जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों को किया जाए जागरूक- मुख्य सचिव

अनुदानित उर्वरकों के डायवर्जन पर लगेगी रोक, एफएफएस पोर्टल से होगा पारदर्शी वितरण

जयपुर (कासं)। प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को यूरिया एवं डीएपी की सुगम, समयबद्ध एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 के दौरान प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की मांग, आपूर्ति एवं जिलेवार उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों एवं उर्वरक कंपनियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में यूरिया एवं डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बुवाई के दौरान खाद की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग एवं उर्वरक निर्माता कंपनियां समन्वित प्रयास करते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करें। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आवंटन के अनुरूप राज्य को आपूर्ति नहीं करने वाली कंपनियों के आवंटन में कटौती कर उसे बेहतर आपूर्ति करने वाली सक्षम कंपनियों को अंतरित करने के लिए कृषि विभाग केंद्र सरकार से समन्वय एवं पत्राचार करे।



बैठक के आरंभ में कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने प्रदेश में रबी एवं खरीफ 2026-27 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की मांग, आपूर्ति एवं उपलब्धता की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया की आपूर्ति व उपलब्धता संतोषजनक स्थिति में है।

खरीफ के दौरान आवंटन के विरुद्ध 112 प्रतिशत आपूर्ति दर्ज की गई तथा वर्तमान में भी प्रारंभिक स्टॉक व निरंतर आवक के चलते 9.64 लाख मीट्रिक टन की सुदृढ़ उपलब्धता बनी हुई है। डीएपी के संदर्भ में उन्होंने अवगत कराया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद राज्य में आपूर्ति तंत्र को निरंतर सक्रिय रखा गया है तथा अधिकांश जिलों में 8 से 10 दिन का अग्रिम बफर स्टॉक सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने गत 6 अक्टूबर की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना, कंपनियों द्वारा आवंटन के विरुद्ध कम आपूर्ति पर भारत सरकार से पत्राचार, एफएफएस पोर्टल के राज्यव्यापी क्रियान्वयन तथा यूरिया डायवर्जन पर पुलिस व राजस्व तंत्र के साथ की गई संयुक्त कार्रवाइयों की प्रगति से भी अवगत कराया।

अनुदानित उर्वरकों के औद्योगिक डायवर्जन एवं कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई-

बैठक में कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने उर्वरकों के अवैध डायवर्जन, भंडारण एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में संचालित अभियान की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि फर्टिलाइजर डीलर्स की रियल-टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग के तहत अब तक 12 हजार 141 डीलर्स का सघन निरीक्षण किया गया है। अभियान के दौरान 193 नमूने लिए गए, 1 हजार 282 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 64 प्रतिष्ठानों पर बिक्री रोक लगाई गई तथा 93 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

जयपुर में गूंजेंगे साहिर के नगमे 'वो सुबह कभी तो आएगी'

28 नवंबर को होगा जश्ने-ए-साहिर

जयपुर (कासं)। देशभक्ति और इंसानियत के शायर साहिर लुधियानवी की याद में विकल्प नाट्य संगठन की ओर से शनिवार, 28 नवंबर को सायं 5:30 बजे, रंगायन, जवाहर कला केंद्र में सास्कृतिक संध्या 'जश्ने-ए-साहिर - वो सुबह कभी तो आएगी' का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रख्यात पत्रकार राजेश बादल द्वारा लिखित साहिर लुधियानवी की जीवनी 'ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया' का लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर राजेश बादल इस महान शायर और नगमानिगार साहिर का जिंदगीनामा अपनी ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

इस अवसर पर साहिर के अमर नगमों की संगीतमय प्रस्तुति भी होगी, जिसमें शहर के नामचीन गायक कलाकार राजीव भट्ट, रेखा भट्ट, मनमोहन सिंह रावत, केशव तैलंग, यशवर्धन, ओम गोस्वामी, डॉ. कविता माथुर, पप्पू सिंह, भारती शर्मा और मनोहर पोपली अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगे, शामिल होंगे। मुख्य आयोजक विकल्प के अध्यक्ष एम एल गोयल ने बताया कि इस संध्या का उद्देश्य नई पीढ़ी को साहिर की शायरी, उनके विचारों और मानवतावादी दृष्टिकोण से जोड़ना है।

'वो सुबह कभी तो आएगी' सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि उम्मीद, बराबरी और बेहतर कल की आस का प्रतीक है। यह कार्यक्रम दर्शक कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स और राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के सह आयोजक प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव प्रेमचंद गांधी ने बताया कि वर्षों बाद साहिर लुधियनवी की याद में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जयपुर में होने जा रहा है। कार्यक्रम में दर्शकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा।

देवनानी करेंगे आज अजमेर विधान सभा दीर्घा का लोकार्पण और वेबसाइट का शुभारम्भ

जयपुर। राजस्थान विधान सभा में संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार 26 नवंबर को प्रात: 11:30 बजे विशेष समारोह का आयोजन होगा। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस समारोह में संविधान की महत्ता, लोकतांत्रिक मूल्यों, विधायी परंपराओं तथा संसदीय व्यवस्था के प्रति जागरुकता के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह में संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी राज्य मंत्री संजय शर्मा और डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलगुरू डॉ. निष्ठा जायसवाल को आमंत्रित किया गया है। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित अजमेर विधान सभा दीर्घा तथा अजमेर विधानसभा वेबसाइट का लोकार्पण करेंगे। यह समारोह संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका से आमजन, विशेषकर युवा पीढ़ी को परिचित कराने का प्रयास है। इस दीर्घा में अजमेर विधान सभा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया गया है। जयपुर के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 18 विद्यालयों में अध्ययनरत 252 छात्र-छात्राएं तथा 20 शिक्षक इस समारोह में शामिल होंगे। यह अवसर युवा पीढ़ी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक प्रावधानों, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की समझ विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि यह समारोह संविधान के प्रति सम्मान, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करेगा। दीर्घा का लोकार्पण और वेबसाइट का शुभारंभ विधायी गतिविधियों से संबंधित जान और सूचनाओं को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस का शानदार प्रदर्शन

महिला पाइप बैंड ने जीता स्वर्ण, ब्रास बैंड ने रजत पदक



जयपुर (कासं)। 27वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता-2026 में राजस्थान पुलिस के बैंड दलों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में 16 से 20 नवंबर तक प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस महिला पाइप बैंड ने स्वर्ण और ब्रास बैंड टीम ने रजत पदक जीता है। महिला पाइप बैंड टीम का नेतृत्व बैंड मास्टर पूनम सपेरा ने किया। टीम ने लगातार तीसरे वर्ष पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले टीम ने 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता-2025 में कांस्य और 25वीं प्रतियोगिता-2024 में स्वर्ण पदक जीता था। इसी प्रकार, राजस्थान पुलिस ब्रास बैंड टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। टीम का नेतृत्व बैंड मास्टर योगेन्द्र कुमार ने किया। इससे पहले टीम 24वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता-2023 में रजत पदक जीत चुकी है। प्रतियोगिता में पदक जीतकर जयपुर लौटने पर महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने दोनों बैंड दलों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर डीजी संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रूपिंदर सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती श्वेता धनकड़, उप महानिरीक्षक पुलिस कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस बैंड वादकों को प्रोत्साहित किया।

सफाई व्यवस्था पर महापौर का एक्शन मोड

हर अधिकारी, कर्मचारी की जबावदेही होगी तय, लापरवाही करने पर होगी सख्ती- कोठारी

जयपुर (कासं)। नगर निगम महापौर सुनील कोठारी ने बुधवार को शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन के विभिन्न स्थानों की सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ निरीक्षण दोपहर 2 बजे तक चला। जिसमें 15 से अधिक स्थानों की सफाई व्यवस्था जांची गई। करीब 5 घंटे चले सफाई निरीक्षण में महापौर ने ओपन कचरा डिपो हटाने, नियमित रूप से झाड़ू लगाने, टूटे हुये डस्टबिनों को हटाकर नये डस्टबिन लगाने, सुलभ शौचालयों,में व्यवस्थाओं को ठीक करने, अवैध एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाने सहित निर्देष दिये। निरीक्षण के दौरान पार्षद सुभाष सिंगी, अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) श्रीमती शैफाली कुषवाहा, उपायुक्त (स्वास्थ्य) ओम थानवी,



उपायुक्त पवन कुमार शर्मा, संबंधित जोन उपायुक्त, उपायुक्त पषु प्रबंधन करणी सिंह, सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

महापौर सुनील कोठारी ने स्टेच्यू सर्किल से औचक सफाई निरीक्षण प्रारंभ किया। जिसके बाद वे तिलक मार्ग पहुंचे वहां पर कई इमारतों, बिल्डिंग एवं सोसायटी के बाहर ओपन कचरा डिपो एवं सीएनडी वेस्ट पड़ा हुआ मिला जिसके लिये महापौर ने मौके पर आमजन को समझाइष की साथ ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था का फीडबैक भी लिया। उसके बाद अषोक उद्यान के आस-पास सफाई व्यवस्था देखी गंदगी देखकर सीएसआई को फटकार लगाई। सी-स्कीम स्थित नाले में डाले जा रहे कचरे पर चालान करने तथा वहां सफाई के निर्देष दिये। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि शहर को स्वच्छ रखना हर नागरिक का दायित्व है इसलिये कचरा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। सड़कों पर अवैध अस्थायी अतिक्रमण ना करें, सफाई एक दिन के लिये नहीं बल्कि नियमित कार्य है यदि हर अधिकारी, कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन व आमजन जागरूकता के साथ शहर को स्वच्छ रखने में भागीदारी निभाये तो शहर स्वच्छ व सुन्दर बन सकेगा।

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक :- तकनीकी/2026-27/2949 - 58 दिनांक :- 19/11/2026

ऑनलाईन निविदा सूचना संख्या 26/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में उपयुक्त श्रेणी में, विभिन्न विभागो में ए एवं एए श्रेणी (सिविल कार्यो) एवं विद्युत कार्यो हेतु नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में उपयुक्त श्रेणी में एवं विभिन्न विभागों में ई.डब्ल्यू.एस.डी.-I कैटेगरी में पंजीबद्ध संवेदको/सप्लायर्स से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रकिया से वेब साईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती हैं।

पार्ट	निविदा की क्र.सं.	ऑनलाईन निविदा विक्रय/डाउनलोड/प्राप्ति तिथि	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि
A	01 से 08	21.11.2026 से 02.12.2026 प्रातः 9.30 से दोपहर 1.00 बजे तक। UBN:UTB2627WSOB00162 - 00169	03.12.2026 को दोपहर 01:00 बजे

नोट :- निविदा सूचना से सम्बन्धित समस्त विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है जो कि आज दिनांक को अपलोड कर दिया गया है। संवेदक द्वारा न्यास कार्यालय में निविदा विक्रय तिथि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है।

अधिशाषी अभियंता

राज.संवाद/सी/26/13627 नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक कैलाश त्रिवेदी के लिए उदय प्रिन्टर्स 43-ए, माली कॉलोनी चांदपोल बाहर जयपुर से मुद्रित एवं डी-38, प्रधानपथ, चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक कैलाश त्रिवेदी* । *पीआईबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार।
फोनः 0141-4038281, Email:- lokjeewanjpr@gmail.com भीलवाड़ा कार्यालयः 207-214, नागौरी गार्डन, लोकजीवन कॉम्पलेक्स, भीलवाड़ा। फोनः 01482-355985, Email:- lokjeewan@gmail.com, मो. 8306792625